gradeup

आर्थिक और सामाजिक विकास समसामयिकी अप्रैल 2020

Prep Smart. Score Better. Go gradeup

www.gradeup.co

आर्थिक और सामाजिक विकास सम्बन्धी घटनाएँ

फुली एक्सेसिबल रूट (एफ.ए.आर.)

खबरों में क्यों है?

• भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने गैर-निवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड में निवेश करने में सक्षम बनाने हेतु फुली एक्सेसिबल रूट (एफ.ए.आर.) नामक एक पृथक चैनल की शुरूआत की है।

• ये विशेष प्रतिभूतियाँ परिपक्वता तक किसी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ.पी.आई.) सीमा को आकर्षित नहीं करेंगी और यह भारतीय जी-सेक की ओर पहला कदम है, जिसे वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में सूचीबद्ध किया जाएगा क्यों कि केंद्र, विदेशी बाजारों में सस्ती तरलता को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत है।

फुली एक्सेसिबल रूट के संदर्भ में जानकारी

• योग्य निवेशक किसी भी निवेश सीमा के अधीन हुए बिना निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।

• यह योजना दो मौजूदा मार्गों के साथ संचालित होगी।

• मध्यम अवधि रूपरेखा (एम.टी.एफ.)

• स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वी.आर.आर.)

पृष्ठभूमि

• यह कदम केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई घोषणा का अनुसरण करता है कि केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ निश्चित निर्दिष्ट श्रेणियां बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण रूप से अनिवासी निवेशकों के लिए खोली जाएंगी।

• तदनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों में गैर-निवासियों द्वारा निवेश के लिए एक अलग मार्ग अर्थात फुली एक्सेसिबल रूट (एफ.ए.आर.) शुरू किया गया है।

• इससे गैर-निवासियों को भारत सरकार के प्रतिभूति बाजारों तक पहुंच में आसानी होगी और वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में समावेशन की सुविधा होगी।

• इससे सरकारी बॉन्डों में स्थायी विदेशी निवेश के अंतर्वाह को बढ़ावा मिलेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- अर्थशास्त्र

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

मूल प्रमाणपत्र

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों के लिए 'मूल प्रमाण पत्र' जारी करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है।

मूल प्रमाण पत्र क्या है?

• मूल प्रमाण पत्र (सी.ओ.), एक दस्तावेज है जिसमें यह घोषित किया जाता है कि किस देश में उपभोक्ता उत्पाद या वस्तु का निर्माण किया गया था। मूल प्रमाण पत्र में उत्पाद, उसके गंतव्य और निर्यात के देश के बारे में जानकारी शामिल है।

• सीमा पार व्यापार के लिए कई संधि समझौतों द्वारा आवश्यक है, सी.ओ. एक महत्वपूर्ण फॉर्म है क्योंकि यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि कुछ निश्चित उत्पाद आयात के योग्य हैं या उत्पाद, शुल्कों के अधीन हैं।

मूल प्रमाण पत्र के दो प्रकार

सी.ओ. के दो प्रकार: गैर-अधिमान्य और अधिमान्य हैं।

• **गैर-अधिमान्य सी.ओ**. को "साधारण सी.ओ." के रूप में भी जाना जाता है, यह इंगित करता है कि उत्पाद, देशों के बीच व्यापार समझौते के अंतर्गत कम टैरिफ या टैरिफ-मुक्त उपचार के लिए योग्य नहीं है। समान प्रकार से, **अधिमान्य सी.ओ**. घोषित करता है कि उत्पाद इस योग्य हैं।

महत्व

• मुक्त व्यापार समझौतों (एफ.टी.ए.) के अंतर्गत शुल्क रियायतों का दावा करने के लिए यह दस्तावेज़ महत्वपूर्ण है।

• यह प्रमाण पत्र, यह साबित करने के लिए आवश्यक है कि उनका माल कहाँ से आता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- अर्थशास्त्र

स्रोत- ई.टी.

बैकएसॉरेंस समझौता

खबरों में क्यों है?

• बीमा विनियामक, भारत के बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने हाल ही में मेगा बैंक विलय की कवायद से उभरे चार बैंकों को उनके साथ सम्मिलित ऋणदाताओं के मौजूदा बैकएसॉरेंस समझौते के साथ एक वर्ष तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की है।

बैकएसॉरेंस के संदर्भ में जानकारी

• इसका अर्थ बैंकों के माध्यम से बीमा उत्पाद बेचना है। बैंक और बीमा कंपनी एक साझेदारी करती हैं, जिसमें बैंक अपने ग्राहकों को बीमा कंपनी के बीमा उत्पाद बेचता है।

दोहरे-लाभ

• एक ओर, बैंक, बीमा कंपनी से ब्याज की आय के अतिरिक्त शुल्क राशि (गैर-ब्याज आय) अर्जित करता है जब कि दूसरी ओर, बीमा फर्म अपनी बाजार पहुंच और ग्राहकों को बढ़ाती है।

नियम

• भारत सरकार अधिसूचना (बैंकिंग विनियमन अधिनियम) दिनांक 3 अगस्त, 2000 ने बैकएसॉरैंस अनुमति प्रदान की है।

• बैकएसॉरैंस विनियमों के अनुसार, एक बैंक केवल तीन: जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के उत्पादों का विपणन कर सकता है।

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

• यह एक स्वायत्त, संवैधानिक निकाय है जो भारत में बीमा और पुन: बीमा उद्योगों को विनियमित और संवर्धित करता है।

• यह बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा गठित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा पारित संसद का एक अधिनियम है।

• इरडा, 10 सदस्यीय निकाय है, जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

हेलीकाप्टर मनी

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक को सुझाव दिया है कि वह राज्य सरकारों को वर्तमान संकट से बचाने और भारत में आर्थिक गतिविधि को शुरू करने में मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा को अपना सकता है।

हेलीकाप्टर मनी के संदर्भ में जानकारी

• हेलीकॉप्टर मनी शब्द को अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडमैन ने अपने पेपर "द ऑप्टिमेट क्वांटिटी ऑफ मनी" में गढ़ा था।

• यह एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य बड़ी मात्रा में धन की छपाई करके और इसे जनता में वितरित करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है।

लाभ

• मांग वृद्धि में वृद्धि

• अन्य के बीच मुद्रास्फीति में वृद्धि

चुनौतियां

• इससे अतिस्फीति हो सकती है।

• अन्य के बीच मुद्रा का अवमूल्यन

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3-अर्थशास्त्र

स्रोत- ई.टी.

विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2020

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है।

विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में जानकारी

• यह रिपोर्ट वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है।

• इसका उद्देश्य सदस्य देशों के आर्थिक विकास का विश्लेषण और पूर्वानुमान प्रदान करना और जोखिमों और अनिश्चितता पर प्रकाश डालना है।

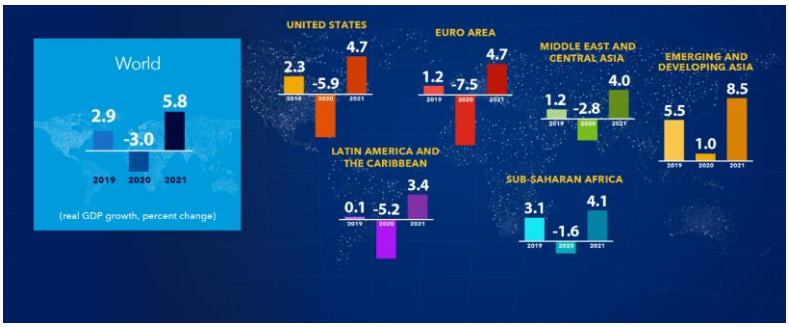

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

• रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप, वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2020 में तेजी से -3 प्रतिशत तक घटने का अनुमान है, जो 2008-09 के वित्तीय संकट के दौरान की गिरावट से बेहद खराब है।

• आई.एम.एफ. ने अपने 2020 विश्व आर्थिक आउटलुक में, 2021 में आंशिक रूप से पलटाव की भविष्यवाणी की है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के 5.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

• अमेरिकी अर्थव्यवस्था वर्ष 2020 में 5.9 प्रतिशत घटेगी, फंड के सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य के अंतर्गत वर्ष 2021 में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पलटाव का अनुमान है।

• वर्ष 2020 में यूरोजोन अर्थव्यवस्थाओं में 7.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी, जिसमें अत्यधिक प्रभाव के साथ इटली की जी.डी.पी. में 9.1 प्रतिशत की गिरावट और स्पेन में 8.0 प्रतिशत की गिरावट और जर्मनी में 7.0 प्रतिशत की गिरावट और फ्रांस में 7.2 प्रतिशत की गिरावट होगी।

• इसने भविष्यवाणी की है कि यूरो-क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं वर्ष 2021 में 4.7 प्रतिशत की अमेरिकी विकास दर से मेल खाएंगी।

• चीन की अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 में 9.2 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है।

• भारत की वर्ष 2020 के वित्तीय वर्ष की वृद्धि के सकारात्मक क्षेत्र में रहने की उम्मीद है, लेकिन लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाएं, जो अभी भी बढ़ते हुए कोरोनोवायरस के प्रकोप का सामना कर रही हैं, उनमें 5.2 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में जानकारी

• आई.एम.एफ., 189 देशों का एक संगठन है।

• इसका मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका में स्थित है।

• आई.एम.एफ. की आधिकारिक भाषा- चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी है।

उद्देश्य

यह निरंतर रूप से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना चाहता है:

A. वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना

B. वित्तीय स्थिरता सुरक्षित करना

C. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करना

D. उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

E. पूरे विश्व में गरीबी को कम करना

आई.एम.एफ. द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्टें

A. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

B. राजकोषीय मॉनिटर

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- अर्थशास्त्र

स्रोत- आई.एम.एफ. वेबपेज

अनिश्चित समय के लिए मुद्रा विनिमय

खबरों में क्यों है?

• भारत, डॉलर स्वैप लाइन को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काम कर रहा है जो इसके बाहरी खाते के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा और धन के अचानक बहिर्वाह की स्थिति में एक अतिरिक्त सहयोग प्रदान करेगा।

भारत का परिदृश्य

• भारत के पास पहले से ही जापान के साथ 75 बिलियन डॉलर की द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप लाइन है, जिसमें चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा डॉलर भंडार है।

• भारतीय रिज़र्व बैंक भी $ 2 बिलियन के कुल कोष के भीतर सार्क क्षेत्र में केंद्रीय बैंकों को इसी तरह की स्वैप लाइनें प्रदान करता है।

एक मुद्रा विनिमय क्या है?

• एक मुद्रा विनिमय, दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं (दोनों देशों या किसी भी कठिन मुद्रा) का विनिमय करने हेतु एक समझौता या अनुबंध है। यह हमेशा दो केंद्रीय बैंकों के बीच होता है।

• मुद्रा विनिमय समझौता, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकता है।

मुद्रा विनिमय का क्या उद्देश्य है?

• मुद्रा विनिमय का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और अन्य जोखिमों से बचना है।

• केंद्रीय बैंक और सरकारें विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित करने के लिए विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा विनिमय में संलग्न हैं।

सामान्यत:, मुद्रा विनिमय समझौते पांच प्रकार के होते हैं और ये उनकी प्रकृति और विनियमित की गई मुद्राओं की स्थिति पर निर्भर करता है।

A. प्रतिभूतियों के लिए नकदी बनाम नकद के लिए विनिमय नकद

B. विनिमय सशर्त बनाम बिना शर्त विनिमय

C. दोनों तरफ विनिमय आरक्षित मुद्राएं

D. गैर-आरक्षित मुद्रा के लिए विनिमय आरक्षित मुद्रा

E. दोनों तरफ गैर-आरक्षित मुद्राओं का विनिमय करना

संबंधित लाभ क्या हैं?

• ये विनिमय परिचालन, कोई विनिमय दर या अन्य बाजार जोखिम नहीं उठाते हैं, क्योंकि लेनदेन की शर्तें पहले से निर्धारित होती हैं।

• विनिमय दर जोखिम की अनुपस्थिति इस प्रकार की सुविधा का प्रमुख लाभ है।

• यह तीसरी मुद्रा के खिलाफ अस्थिरता के जोखिम को कम करता है और कई मुद्रा विनिमय में शामिल शुल्कों को समाप्त करता है।

• विनिमय समझौते, संभव अल्पकालिक तरलता असमानता को संबोधित करने में मदद करता है और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के पूरक में मदद करेगा।

• बैलेंस ऑफ पेमेंट (बी.ओ.पी.) से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए इस तरह की स्वैप लाइन की उपलब्धता घरेलू मुद्रा पर काल्पनिक हमलों को रोकती है और विनिमय दर की अस्थिरता को प्रबंधित करने की आर.बी.आई. की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा देती है।

नोट: शुरूआती मुद्रा विनिमय, अमेरिकी फेडरल रिजर्व और सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस के बीच 28 फरवरी, 1962 को हस्ताक्षरित किया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय समिति (आई.एम.एफ.सी.) की पूर्ण बैठक में भाग लिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) की मंत्रिस्तरीय-स्तरीय समिति है।

एक पूर्ण सत्र क्या है?

• पूर्ण सत्र या विस्तृत बैठक, एक सम्मेलन का एक सत्र होता है जिसमें सभी दलों के सभी सदस्यों को भाग लेना होता है।
• इस तरह के सत्र में सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है, जिसमें प्रमुख बिंदुओं से लेकर पैनल चर्चा तक शामिल हो सकती है और यह आवश्यक रूप से प्रस्तुति की विशिष्ट शैली या विचारशील प्रक्रिया से संबंधित नहीं है।

पृष्ठभूमि
• आई.एम.एफ.सी., वर्ष में दो बार आयोजित होती है, एक बार अक्टूबर में फंड-बैंक वार्षिक बैठक के दौरान और फिर अप्रैल में वसंत बैठकों के दौरान आयोजित होती है।
• यह समिति वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले आम चिंता के मुद्दों पर चर्चा करती है और आई.एम.एफ. को अपने काम की दिशा में सलाह देती है।
बैठक का एजेंडा
• बैठक में चर्चा आई.एम.एफ. के प्रबंध निदेशक की वैश्विक नीति एजेंडा पर आधारित थी, जिसका शीर्षक "असाधारण टाइम्स- असाधारण कार्रवाई" था।
• सदस्यों ने आई.एम.एफ. के संकट-प्रतिक्रिया पैकेज पर वैश्विक तरलता और सदस्यों के वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी टिप्पणी की है।
भारत में किए गए उपाय हैं:
• केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य संकट की प्रतिक्रिया के साथ-साथ इसके प्रभाव को कम करने के लिए भारत में किए गए विभिन्न उपायों को रेखांकित किया है। इस संबंध में, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा $ 2 बिलियन (15,000 करोड़ रुपये) का आवंटन किया गया है।
• गरीबों और कमजोर लोगों की कठिनाईयों को कम करने के लिए $ 23 बिलियन (1.70 लाख करोड़ रुपये) की राशि की सामाजिक सहायता उपायों की एक योजना की घोषणा की गई है।
• संवैधानिक और विनियामक अनुपालन मामलों में फर्मों को राहत का प्रावधान किया गया है।
• आर.बी.आई. द्वारा मौद्रिक नीति को आसान बनाना और ऋण किस्तों पर तीन महीने की मोहलत प्रदान की गई है।
टॉपिक- जी.एस. पेपर 3-अर्थशास्त्र
स्रोत- पी.आई.बी.

सरकार ने पड़ोसी देशों से एफ.डी.आई. के लिए अनिवार्यता को मंजूरी दी है।

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद घरेलू कंपनियों के "अवसरवादी अधिग्रहण" को रोकने के लिए भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से विदेशी निवेश के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दी है, यह एक ऐसा कदम है जो चीन से एफ.डी.आई. को प्रतिबंधित करेगा।

• जो देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं वे चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान हैं।

सरकार द्वारा अपनाए गए परिवर्तन

• उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.) के अनुसार, किसी देश की एक इकाई, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है या जहां भारत में निवेश का लाभकारी मालिक स्थित है या ऐसे किसी भी देश का नागरिक है, वह केवल सरकारी मार्ग के अंतर्गत ही निवेश कर सकता है।

• प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में एक इकाई में किसी भी मौजूदा या भविष्य की एफ.डी.आई. के स्वामित्व के हस्तांतरण की स्थिति के परिणामस्वरूप पड़ोसी देशों से सभी एफ.डी.आई. के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक होनी चाहिए।

• पाकिस्तान का नागरिक या पाकिस्तान में शामिल एक इकाई, केवल सरकारी मार्ग के अंतर्गत, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और विदेशी निवेश के लिए निषिद्ध क्षेत्रों/ गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में निवेश कर सकती है।

भारत में एफ.डी.आई.

• एफ.डी.आई., भारत के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मौद्रिक स्रोत है। 1991 के संकट के परिणामस्वरूप भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी और तब से देश में एफ.डी.आई. लगातार बढ़ रही है।

• ग्रीनफील्ड एफ.डी.आई. रैंकिंग में भारत विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर है।

वे मार्ग जिनके माध्यम से भारत को एफ.डी.आई. मिलती है

'स्वचालित मार्ग' के क्या प्रावधान हैं?

• अनिवासी या भारतीय कंपनी को एफ.डी.आई. के लिए आर.बी.आई. या भारत सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

• अधिकांश क्षेत्रों में एफ.डी.आई. को स्वचालित मार्ग के माध्यम से अनुमति दी जाती है, कुछ निश्चित क्षेत्रों जैसे रक्षा, दूरसंचार, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स और बीमा, विदेशी निवेशकों के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यकता होती है।

सरकार का मार्ग क्या है?

• सरकार की मंजूरी अनिवार्य होती है।

• कंपनी को विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से एक आवेदन दायर करना होगा, जो एकल-खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है।

• फिर आवेदन को संबंधित मंत्रालय को भेज दिया जाता है, जो वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.) के परामर्श से आवेदन को मंजूरी पदान करेगा/ अस्वीकार कर देगा।

• डी.पी.आई.आई.टी., मौजूदा एफ.डी.आई. नीति के अंतर्गत आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी करेगा।

वे क्षेत्र जहां एफ.डी.आई. निषिद्ध है:

• ऐसे नौ क्षेत्र हैं जहां एफ.डी.आई. निषिद्ध है और जिसमें लॉटरी व्यवसाय, जुआं और सट्टेबाजी, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट व्यवसाय और तंबाकू के साथ सिगार, चेरूट, सिगारिल और सिगरेट का निर्माण शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

रिवर्स रेपो दर, अर्थव्यवस्था में बेंचमार्क ब्याज दर बन रही है।

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, आर.बी.आई. द्वारा उठाए गए नीतिगत कदम इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं कि कोविड 19 संकट के बीच रिवर्स रेपो दर, अब नई बेंचमार्क दर बन गई है।

रेपो और रिवर्स रेपो दर के संदर्भ में जानकारी:

• रेपो (पुनर्खरीद समझौते) दर, वह दर है जिस पर आर.बी.आई. छोटी अवधि के लिए बैंकिंग प्रणाली (या बैंकों) को पैसा उधार देता है।

• रिवर्स रेपो दर, वह दर है जिस पर बैंक, आर.बी.आई. के पास अपना पैसा रख सकते हैं।

• दोनों परिदृश्यों में लेनदेन बांड के माध्यम से होता है- एक पक्ष बाद में निर्दिष्ट तिथि पर उन्हें वापस खरीदने (या उन्हें पुनर्खरीद) करने के वादे के साथ दूसरे पक्ष को बांड बेचता है।

• रेपो दर, धन जुटाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है।

सामान्य परिदृश्य:

• सामान्य परिस्थितियों में, जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है तो रेपो दर बाजार में बेंचमार्क ब्याज दर होती है क्योंकि यह सबसे कम ब्याज दर होती है जिस पर फंड उधार लिया जा सकता है।

• यह अर्थव्यवस्था में अन्य सभी ब्याज दरों के लिए फ्लोर रेट बनाता है- उदाहरण के लिए, जिस ब्याज दर पर उपभोक्ताओं को कार ऋण का भुगतान करना होता है या वह ब्याज दर, जो आप सावधि जमा आदि पर अर्जित करते हैं।

रिवर्स रेपो दर, बेंचमार्क दर बन रही है:

• बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता का मतलब है कि मार्च और अप्रैल के प्रारंभिक 15 दिनों के दौरान बैंक, रेपो (फंड उधार लेने हेतु) के बजाय केवल रिवर्स रेपो (आर.बी.आई. के साथ धन रखने के लिए) का उपयोग कर रहे हैं।
• 15 अप्रैल तक, आर.बी.आई. के पास बैंकों के 7 लाख करोड़ रुपये का पैसा था, जो उसने अब बंद कर दिया है।
• दूसरे शब्दों में, रिवर्स रेपो दर, अर्थव्यवस्था में सबसे प्रभावशाली दर बन गई है।
• इस मुद्दे के कारण, केंद्रीय बैंक ने पिछले तीन हफ्तों के अंतराल में रेपो (ग्राफ देखें) की तुलना में रिवर्स रेपो दर में दो बार कटौती की है।

इस कदम की प्रभावकारिता:

• यह सब भारत में उपभोक्ता मांग के पुनरूद्धार पर निर्भर करता है।
• यदि नॉवेल कोरोनावायरस बीमारी के प्रकोप से प्रेरित व्यवधान लंबे समय तक जारी रहते हैं, उपभोक्ता मांग शांत बनी रहती है और व्यवसायों को नए निवेश करने के लिए बड़े उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
• यदि उपभोक्ता की मांग में तेजी आती है, तो ऋण की मांग भी बढ़ेगी।
• बैंकों के परिप्रेक्ष्य से, उन्हें नए ऋणों के बारे में आश्वस्त होना भी महत्वपूर्ण है, उन्हें एन.पी.ए. में नहीं बदलने देना और उनके पास पहले से ही उच्च स्तर के बुरे ऋण उपलब्ध हैं।
• जब तक बैंक एक आर्थिक बदलाव की संभावनाओं के बारे में आश्वस्त महसूस नहीं करते हैं तब तक रिवर्स रेपो दरों में कटौती का बहुत कम प्रभाव हो सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- अर्थशास्त्र
स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

टी.एल.टी.आर.ओ. 2.0 के अंतर्गत बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र राहत

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टी.एल.टी.आर.ओ.) 2.0 के अंतर्गत लघु एवं मध्यम आकार के एन.बी.एफ.सी. और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों में निवेश करने वाले बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र राहत प्रदान की है।
• प्राथमिकता वाले क्षेत्र की प्रतिबद्धता का आकलन करते हुए इन निवेशों की गणना बैंक के समायोजित गैर-खाद्य बैंक ऋण के हिस्से के रूप में नहीं की जाएगी।

Gradeup Green Card
Unlimited Access to 100+ Mock Tests
UPSC CSE, UPSC EPFO & State PCS Exams
Enrol Now

आर.बी.आई. के दिशानिर्देश

• आर.बी.आई. ने निर्दिष्ट किया था कि टी.एल.टी.आर.ओ. 2.0 योजना के अंतर्गत, बैंकों को 500 करोड़ और उससे कम की संपत्ति आकार के छोटे एन.बी.एफ.सी., 500 करोड़ से 5000 करोड़ के बीच की संपत्ति आकार के मध्यम आकार के एन.बी.एफ.सी. और एम.एफ.आई. के बांड में कुल फंड का कम से कम आधा निवेश करना होगा। बैंको को वर्तमान में कृषि, छोटे व्यवसायों, शिक्षा, सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अपने कुल ऋण का 40% आवंटित करना है, जिन्हें सामूहिक रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है।

• यह छूट केवल टी.एल.टी.आर.ओ. 2.0 के अंतर्गत प्राप्त फंड पर लागू होती है और आर.बी.आई. को उम्मीद है कि इससे इन एन.बी.एफ.सी. और एम.एफ.आई. में बैंकों के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

दीर्घकालिक रेपो परिचालन के संदर्भ में जानकारी

• यह एक ऐसा उपकरण है, जिसके अंतर्गत आर.बी.आई. प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को एक वर्ष से तीन वर्ष तक के ऋण प्रदान करता है।

उद्देश्य

• अल्पकालिक ब्याज दरों को पॉलिसी रेपो दर के साथ सिंक में बनाए रखना

लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टी.एल.टी.आर.ओ.) के संदर्भ में जानकारी

• इसे आर.बी.आई. द्वारा पेश किया गया था, जिसके अंतर्गत बैंक तीन वर्ष तक के वित्तपोषण तक पहुँच सकते हैं और इसका उपयोग निवेश-ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक दस्तावेजों और ऋणपत्रों में निवेश करने के लिए कर सकते हैं।

• इसमें से, बैंकों को प्राथमिक बाजार जारीकर्ता से योग्य उपकरणों के वृद्धिशील स्वामित्व का 50 प्रतिशत तक खरीदना आवश्यक है और शेष द्वितीयक जारीकर्ता से खरीदना आवश्यक है, जिसमें म्यूच्युअल फंड और एन.बी.एफ.सी. शामिल हैं।

• एल.टी.आर.ओ., ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर आयोजित किए जाते हैं जो आर.बी.आई. का प्रमुख बैंकिंग समाधान है।

टी.एल.टी.आर.ओ. का महत्व

• यह आर.बी.आई. द्वारा वित्तीय संस्थानों सहित कंपनियों की मदद करने के लिए पेश किया गया था, जो कोरोनोवायरस प्रकोप और लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर उनकी नकदी प्रवाह की समस्याओं का समाधान करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- अर्थशास्त्र

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

ऑपरेशन ट्विस्ट

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने लंबी अवधि की पैदावार को सुगम बनाने के लिए एक बोली में सरकारी बॉन्ड की एक साथ खरीद और बिक्री की घोषणा की है।

उद्देश्य:

• इसका उद्देश्य तरलता और बाजार की स्थितियों का प्रबंधन करना है: वर्तमान और विकसित होती तरलता और बाजार की स्थितियों की समीक्षा पर आर.बी.आई. ने सरकारी बांडों की एक साथ खरीद और बिक्री करने का निर्णय लिया है, जो कि कोविड-19 से प्रभावित हैं।

खुला बाजार परिचालन:

• आर.बी.आई. वर्ष 2026 से 2030 के बीच परिपक्व होने वाले 10,000 करोड़ रूपए मूल्य के बॉन्ड खरीदेगा और समान संख्या में टी-बिल बेचेगा।

• ऐसे खुले बाज़ार परिचालन को 'ऑपरेशन ट्विस्ट' के रूप में जाना जाता है।

• केंद्रीय बैंक ने ऑपरेशन ट्विस्ट का पहली बार इस्तेमाल पिछले वर्ष दिसंबर में किया था।

आर.बी.आई. के कदम का प्रभाव

• 10 वर्ष के बांड पर उपज में 20 आधार अंकों की गिरावट आई है।

• यह कदम बैंकों को अपने ग्राहकों को ब्याज दरों में कटौती के लाभों को प्रेषित करने हेतु प्रेरित करके मौद्रिक संचरण की प्रक्रिया में भी मदद करेगा।

• आर.बी.आई. ने हाल ही में मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर या रेपो दर को 75 बी.पी.एस. घटाकर 4.4% कर दिया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा (एस.एल.एफ.-एम.एफ.)

खबरों में क्यों है?

• हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक विशेष तरलता खिड़की की घोषणा की है जिसे विशेष तरलता सुविधा कहते हैं, ऋण फंड सेगमेंट में उथल-पुथल से प्रभावित होने वाले म्यूचुअल फंड को जमानत पर छुड़ाने हेतु 50,000 करोड़ रूपए के म्यूचुअल फंड के लिए सुविधा प्रदान की है, इस उथल-पुथल सेगमेंट के कारण फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड द्वारा छह क्रेडिट रिस्क फंड को बंद कर दिया गया है।

म्यूचुअल फंड खिड़की के लिए यह विशेष तरलता सुविधा कैसे काम करती है?

• एस.एल.एफ.-एम.एफ. के अंतर्गत, आर.बी.आई. ने निर्धारित रेपो दर पर 90 दिनों की अवधि का रेपो परिचालन करेगा।

• एस.एल.एफ.-एम.एफ. ऑन-टैप और ओपन-एंडेड है और बैंक 11 मई तक या आवंटित राशि का उपयोग करने तक, जो भी पहले हो, वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिए अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

बैंक इस पैसे का क्या करेंगे?

• बैंक, म्यूचुअल फंड में ऋण का विस्तार कर सकते हैं और एम.एफ. द्वारा रखे गए निवेश स्तर के वाणिज्यिक बॉन्ड, वाणिज्यिक दस्तावेजों (सी.पी.), ऋणपत्रों और जमा के प्रमाणपत्रों (सी.डी.) के संपार्श्विक के विरूद्ध रेपो की प्रत्यक्ष खरीद कर सकते हैं। एस.एल.एफ.-एम.एफ. के अंतर्गत लिया गया तरलता समर्थन, परिवक्वता के रूप में रखे गए (एच.टी.एम.) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यहां तक कि एच.टी.एम. पोर्टफोलियो में शामिल करने हेतु स्वीकृत कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक क्यों न हो।

प्रस्ताव की विशेषताएं

• इस सुविधा के अंतर्गत ऋण की बड़े ऋण ढांचे के अंतर्गत गणना नहीं की जाएगी।

• एस.एल.एफ.-एम.एफ. के अंतर्गत अधिगृहीत और एच.टी.एम. श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लक्ष्यों/ उप-लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए समायोजित गैर-खाद्य बैंक ऋण (ए.एन.बी.सी.) की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

• एस.एल.एफ.-एम.एफ. के अंतर्गत एम.एफ. को बढ़ाए गए समर्थन को बैंकों की पूंजी बाजार जोखिम सीमा से मुक्त किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू + इकोनॉमिक टाइम्स

केयर्स कार्यक्रम

खबरों में क्यों है?

• भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, जो नॉवेल कोरोनावायरस वायरस (कोविड-19) महामारी की प्रतिक्रिया में सरकार का समर्थन करेगा।

• केयर्स कार्यक्रम सरकार की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले समर्थन के रूप में प्रदान किया गया है।

इस धनराशि का उपयोग कहां होगा?

• इस धनराशि का उपयोग परीक्षण-निगरानी-उपचार क्षमता को तेजी से बढ़ाने के लिए कोविड-19 रोकथाम योजना को लागू करने के लिए किया जाएगा।
• यह अगले तीन महीनों में 800 मिलियन से अधिक लोगों की सुरक्षा के लिए गरीब, कमजोर, महिलाओं और वंचित समूहों हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
• एशियाई विकास बैंक की वित्तीय और तकनीकी सहायता मार्च, 2020 में शुरू किए गए सरकार के दूरगामी आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन में योगदान देगी।

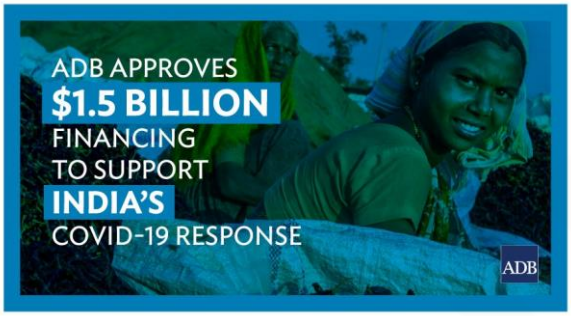

एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) के संदर्भ में जानकारी
• यह 19 दिसंबर, 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है।
• इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है।
उद्देश्य
• एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
सदस्य
• अब इसके 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत के और 19 सदस्य बाहर के हैं।
• ए.डी.बी. में अमेरिका के बाद जापान का शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात है।
नोट:
• हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने एशियाई विकास आउटलुक 2019 प्रकाशित किया है।
• इसमें, ए.डी.बी. ने निवेश की मांग में अपेक्षित वृद्धि की तुलना में धीमी गति के कारण वर्ष 2019-20 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया है।
• वित्त वर्ष 2020-21 में विकास दर 7.3% रहने की संभावना है।
टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- अर्थशास्त्र
स्रोत- पी.आई.बी.

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

खबरों में क्यों है?
• हाल ही में, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना को अधिसूचित किया है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

• यह विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवा बाजार को विनियमित करने हेतु स्थापित किया गया था।

संरचना

इसमें नौ सदस्य शामिल हैं:

• अध्यक्ष

• आर.बी.आई., सेबी, इरडा, पी.एफ.आर.डी.ए. प्रत्येक से एक सदस्य

• वित्त मंत्रालय से दो सदस्य

• एक खोज समिति की सिफारिश पर नियुक्त दो अन्य सदस्य

कार्यकाल

• सदस्यों के पास पुनर्नियुक्ति के अधीन तीन वर्ष का कार्यकाल होगा।

कार्य

• यह वित्तीय उत्पादों जैसे कि प्रतिभूतियों, जमा या बीमा, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के अनुबंधों को विनियमित करेगा, जिन्हें एक आई.एफ.एस.सी. में उपयुक्त विनियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है।

शक्तियां:

• संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत संबंधित वित्तीय क्षेत्र विनियामक (आर.बी.आई., सेबी, इरडा, पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां प्राधिकरण द्वारा आई.एफ.एस.सी. में प्रयोग की जा सकती हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- अर्थशास्त्र

स्रोत- इकोनॉमिक्स टाइम्स

gradeup

आर्थिक और सामाजिक विकास समसामयिकी अप्रैल 2020

Prep Smart. Score Better. Go gradeup

www.gradeup.co